दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 11 दिसंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 74

महत्वपूर्ण एवं खास

पुडुचेरी में डिस्कॉम के निजीकरण पर कांग्रेस-द्रमुक राजनीतिक खेल खेलना बंद करें : शेखर

पुडुचेरी(आरएनएस) । केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के निजीकरण पर अन्नाद्रमुक (पश्चिम) के सचिव ओमशक्ति शेखर ने शुक्रवार को कांग्रेस और द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) दोनों पार्टियों को राजनीतिक खेल खेलना बंद करने को कहा। शेखर ने कहा कि कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन द्वारा बिजली वितरण कंपनी के निजीकरण के खिलाफ यहां आंदोलन करने की घोषणा लोगों को ठगने का काम है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में डिस्कॉम के निजीकरण के लिए सभी शुरुआती जरूरी काम यहां कांग्रेस-द्रमुक की पिछली सरकार के दौरान पूरे किए गए थे। सचिव ने कहा राजनीतिक प्रतिशोध के लिए पुडुचेरी में एन आर कांग्रेस-भाजपा सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए कांग्रेस और द्रमुक ने आंदोलन की घोषणा की है।

खेल को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम के हनाहथियाल में कृत्रिम टर्फ बिछाया गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी)ने इस क्षेत्र में खेलों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्र के अत्यधिक प्रतिभाशाली युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिजोरम के हनाहथियाल में कृत्रिम टर्फ बिछाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। परियोजना को 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसकी परियोजना लागत 682.90 लाख रुपये थी, जो एनईसी द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित थी। यह परियोजना मिजोरम राज्य खेल परिषद द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

शराब के नशे में पत्नी का सिर धड़ से कर दिया अलग, पति ने थाने में जाकर किया सरेंडर

नई दिल्ली (आरएनएस)। तेलंगाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद इस शख्स ने पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह वारदात हैदराबाद की है। आरोपी पति की पहचान परवेज के तौर पर की गई है। आरोप है कि परवेज ने इस खौफनाक हत्याकांड को बीती रात अंजाम दिया है। परवेज एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। बताया जा रहा है कि परवेज अपनी पत्नी समरीन की सत्य-निष्ठा पर शक करता था। इन दोनों की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। इस कपल के तीन बच्चे भी हैं। परवेज और समरीन के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। जिसकी वजह से कुछ वर्ष पहले समरीन अपने पति को छोड़ कर चली गई थी। परवेज को शराब पीने की भी बुरी लत थी और समरीन इससे भी काफी परेशान रहती थी। हालांकि, उस वक्त परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद समरीन और परवेज के बीच सबकुछ ठीक हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस कपल के बीच लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया था। परवेज शराब पीकर घर लौटा था और उसने समरीन से लड़ाई शुरू कर दी। आरोप है कि गुस्से में आकर परवेज ने समरीन का गला काट दिया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रात करीब 2 बजे परवेज स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने यह सरेंडर कर दिया।

म्यांमार में 11 लोगों की हत्या पर आक्रोश व्याप्त

म्यांमार। म्यांमार में 11 लोगों को जिंदा जला दिए जाने की खबरों पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना की निंदा की है. सेना ने इन खबरों का खनन किया है लेकिन स्थानीय लोगों ने घटना की पुष्टि की है.सेना के काफिले पर हमले के एक दिन बाद सेना ने सगैंग प्रांत के डोंटाव गांव के रहने वाले 11 लोगों को बांध कर जिंदा जला दिया. मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं. सेना ने इन दावों से इनकार किया है. सैन्य सरकार द्वारा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा षड़यंत्र का सबूत बताया लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने सैनिकों के चले जाने के बाद हाथ बंधी हुई धधकती लाशों को देखा.

सीडीएस जनरल रावत का पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, बेटियों ने पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि

नई दिल्ली (आरएनएस) । देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का शुक्रवार को यहां पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत को सैन्य प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी गयी, जिसके बाद उनकी दोनों पुत्रियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसके साथ ही उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया।

जनरल रावत के साथ एक ही चिता पर उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय ने जनरल रावत अमर रहे के नारों के बीच नम आंखों से उन्हें अंतिम विदायी दी। जनरल रावत, श्रीमती रावत और 11 अन्य सैनिकों की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर

सिंह धामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विदेशी हस्तियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्रीलंका के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेना के कमांडर जनरल शेवेन्द्र सिल्वा, पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एडमिरल रवीन्द्र सी विजेगुणारत्ने, भूटान की सेना के उप प्रमुख अभियान अधिकारी ब्रिगेडियर दोर्जी रिनचेन, नेपाल के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बाल कृष्ण कार्की और बंगलादेश की सेना के प्रधान स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान भी जनरल रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एडमिरल विजेगुणारत्ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में जनरल रावत के कोर्स सहयोगी रहे हैं। अनेक गणमान्य और विशिष्ट जनों ने अंतिम संस्कार से पहले जनरल रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इससे पहले उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ उनके आवास तीन कामराज मार्ग पर रखा गया था, जहां अनेक केन्द्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और विभिन्न विशिष्ट जनों तथा आम लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सेना, नौसेना और वायु सेना के ब्रिगेडियर स्तर के 12 अधिकारी जनरल रावत के पार्थिव शरीर के पास निगरानी के लिए तैनात किए गए थे।

जनरल रावत की अंतिम यात्रा दो बजे उनके आवास से हुई। उनका पार्थिव शरीर सेना के एक विशाल वाहन में रखा गया था जिसे पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। इसके पीछे वाहनों का विशाल काफिला चल रहा था।

अंतिम यात्रा के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के दो-दो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी राष्ट्रीय ध्वजवाहक बनाए गए थे। साथ ही सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी रैंक के कुल 99 अधिकारी तथा तीनों सेनाओं के बैंड के 33 सदस्य आगे-आगे चल रहे थे। तीनों सेनाओं के सभी रैंकों के 99 अधिकारी अंतिम यात्रा को पीछे से एस्कॉर्ट कर रहे थे। अंतिम यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर जनरल रावत और श्रीमती रावत के पोस्टर लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था, जनरल रावत और श्रीमती रावत अमर रहें। सड़क पर बड़ी संख्या में लोग हाथों में जनरल रावत के पोस्टर तथा राष्ट्रीय ध्वज लिये हुए थे। अंतिम संस्कार के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कुल 800 अधिकारी तथा जवान

हेलिकॉप्टर क्रैश मामला : वायुसेना ने किया कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी का गठन

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश के मामले में वायुसेना ने ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी का गठन कर दिया है। यह जांच समिति हेलिकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता लगाएगी। वायुसेना ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके साथ ही एयरफोर्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह जांच तेजी से पूरी होगी और तथ्यों का पता लगाया जाए।

वायुसेना ने अपील की है कि जांच पूरी होने तक मृतकों की पूरी गरिमा रखी जाए और किसी भी तरह की गलत जानकारी या फिर कयासबाजी से बचा जाए। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देते हुए हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी के गठन का ऐलान किया था। इस जांच का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। इस हादसे के तुरंत बाद ही एयरफोर्स ने जांच कमिटी गठित करने का ऐलान कर दिया था। इस अप्रत्याशित हादसे को लेकर हैरानी भी जताई जा रही है क्योंकि जनरल बिपिन रावत जिस एमआई- 17 हेलिकॉप्टर में सवार थे, वह काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में इसकी जांच होना अहम है। गुरुवार को घटनास्थल से हेलिकॉप्टर का ब्लैकबॉक्स बरामद किया गया था।

इसकी जांच से यह पता चल सकेगा कि आखिर अंतिम क्षणों में हेलिकॉप्टर के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्या जानकारी दी थी। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली में हादसे में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुबह ब्रिगेडियर एल.एस. लिडुर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके परिजन और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शव उनके घर में रखा गया है।

86 प्रतिशत लोगों को दी जा चुकी है टीके की कम से कम एक खुराक : मांडविया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 86 प्रतिशत वयस्कों को कोरोना वायरस रोधी टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। सरकार जल्द से जल्द 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने लोकसभा में एनके प्रेमचंद्रन, राजीव रंजन सिंह, मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की। ओमिक्रॉन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर देश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं और पूरी तथ्य सामने आने के बाद आगे कदम उठाया जाएंगे।

टीकाकरण के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द 100 फीसदी टीकाकरण हो जाए। उन्होंने बताया कि भारत में 86 प्रतिशत लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई है । उन्होंने कहा कि सभी सांसद अपने क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को गति देने का प्रयास करें।

उन्होंने टीकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से जुड़े सवाल पर कहा, पूरे अध्ययन के बाद ही टीकों को मंजूरी मिलती है। लेकिन बिना तथ्य के टीका को लेकर कुछ नहीं कहा जाए क्योंकि इससे लोगों बेवजह फिर झिझक पैदा होगी। मांडविया ने कहा कि कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। इनके जिनोम अनुक्रमण के लिए देश में 36 प्रयोगशालाएं हैं।

दुनिया ने अभी पूर्वोत्तर की अपार क्षमता देखी नहीं है : पीयूष गोयल

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 'मेघालयन एज' स्टोर का शुभारंभ करते हुये कहा, दुनिया ने अभी पूर्वोत्तर की अपार क्षमता देखी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेघालय के शहतूत पर पाले जाने वाले कीड़ों से बने रेशम (मलबेरी सिल्क) के अलावा पूर्वोत्तर के शॉल, बांस, हस्तशिल्प और विभिन्न अनोखे उत्पादों का विशाल बाजार बन सकता है, जो न सिर्फ भारतीयों के लिये, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिये आकर्षण होगा। उन्होंने कहा: दुनिया आपका मंच है।

गोयल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत किया: जब तक कि भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी भाग पश्चिमी और दक्षिणी भारत के समकक्ष नहीं आ जायेंगे, देश विकास नहीं कर सकता, और कहा, उनके हृदय में पूर्वोत्तर के विकास की यह प्रतिबद्धता है, ऐसी गहरी अभिलाषा और पूर्वोत्तर के लोगों के बेहतर जीवन की उत्कंठा है कि हम सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य हो गया है कि हम पूर्वोत्तर पर पूरा ध्यान दें और यह देखें कि वहां और क्या-कुछ किया जा

सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी की हृदयस्थली में राज्य के विशिष्ट और उत्कृष्ट स्टोर की सहज शैली की प्रशंसा करते हुये पीयूष गोयल ने एक ऐसे स्टोर की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को बधाई दी, जहां राज्य के 43 हजार से अधिक बुनकरों और स्थानीय शिल्पकारों को एक ही छत के नीचे मेघालय की समृद्ध संस्कृति, विरासत, कला और राज्य के विशिष्ट उत्पादों को पेश करने का मौका मिलेगा। यह स्टोर राज्य के कुटीर उद्योग को भी समर्थन देगा।

गोयल ने कहा, मेघालय के हमारे शिल्पकारों, बुनकरों और दस्तकारों की शानदार कृतियों को देखने के बाद, मैं बस यही कह सकता हूं कि हम जो देख रहे हैं, वह सूरज की एक किरण मात्र है। जो दिख रहा है, उसकी तुलना में आपकी क्षमता अपार है, आपकी योग्यता का पारावार नहीं।

378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म, किसान अपने-अपने घरों को लौटे

नई दिल्ली (आरएनएस)। 13 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इसे खत्म करने का ऐलान किया. सरकार की ओर से पांच मांगों पर भेजे गए प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी.दिल्ली की सीमाओं पर बीते 13 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद और संसद द्वारा आधिकारिक रूप से उन्हें वापस करने के कुछ दिनों बाद, आंदोलनकारी किसानों ने इसे खत्म कर दिया. विरोध ने एनडीए सरकार के लिए एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था. आंदोलन के कारण बीजेपी की प्रमुख सहयोगी अकाली दल ने साथ छोड़ दिया.

मामला देश के सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा था. किसान संगठनों का दावा था कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत भी हो गई. हालांकि सरकार का कहना है कि आंदोलन में कितने किसान मरे उसे आधिकारिक संख्या नहीं पता. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की पांच मांगों पर भेजे गए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी. प्रस्ताव पर गुरुवार को किसान नेताओं की बैठक हुई थी.

बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की. किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक 11 दिसंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर अपने-अपने घरों को लौटने लगेंगे. किसान नेताओं ने इसे अपनी ऐतिहासिक जीत करार दिया है और 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का फैसला किया है. दरअसल केंद्र की ओर से दोबारा भेजे गए मसौदा प्रस्ताव पर किसानों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी थी, उसी प्रस्ताव पर सरकार ने किसानों को अब लिखित में दे दिया है. 15 जनवरी को किसानों की समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में नेता इस बात की समीक्षा करेंगे सरकार सहमत प्रस्तावों को लागू करती है या नहीं. इस बीच, सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट हटाना शुरू भी कर दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बलबीर सिंह राजेवाल ने मीडिया से कहा, आज हम तानाशाह सरकार को हराकर जा रहे हैं. 15 जनवरी को एसकेएम फिर से बैठक करेगा और समीक्षा करेगा कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए मामलों को वापस लेती है और वह अन्य मांगों पर कार्रवाई करती है या नहीं गुरुवार से ही कई किसानों ने दिल्ली की तीन सीमाओं सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बने टेंट हटाने शुरू कर दिए थे. साल भर से अधिक समय से हाईवे पर चले आंदोलन की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस-2021 के अवसर पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) अपने प्रमुख कार्यक्रम ग्राम उजाला का विस्तार करेगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर एक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पहल के तहत पांच राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2,579 गांवों में एलईडी बल्बों को 10 रुपये की उच्च अनुदानित दर पर वितरित किया जाएगा।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस कार्यक्रम को मार्च, 2021 में शुरू किया था। इसके तहत बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले ही 33 लाख से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है। 14 दिसंबर से इस कार्यक्रम को अन्य तीन राज्यों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

सीईएसएल चालू तापदीप्त बल्बों की जगह 7-वाट और 12-वाट के ऊर्जा-कुशल एलईडी बल्ब प्रदान करना जारी रखेगा। ये बल्ब तीन साल की गारंटी अवधि के साथ दिए जाते हैं।

नीति आयोग और भारती फाउंडेशन ने कॉन्वोक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारती एंटरप्राइजेज की लोक-हितैषी शाखा, भारती फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कॉन्वोक 2021-22 की शुरूआत की।

कॉन्वोक एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य भारत भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूलों के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। इस मंच के माध्यम से, सरकारी स्कूलों के स्कूल शिक्षकों/प्रमुखों/प्राचार्यों और भारती फाउंडेशन नेटवर्क के शिक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान-आधारित समाधानों का

उपयोग करने और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर किए गए अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी शिक्षकों और संकायों को अध्ययन प्रक्रिया केन्द्र के रूप में पहचानती है। यह अनुशंसा करता है कि शिक्षकों को शिक्षण के नए दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाएगा जो उनकी कक्षाओं में अध्ययन के नतीजों में सुधार करते हैं। एनईपी प्लेटफॉर्म विकसित करने की सिफारिश करता है ताकि शिक्षक व्यापक प्रसार और प्रतिकृति के लिए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें।

वर्षों से शिक्षक छात्रों की मदद करने के लिए और लॉकडाउन के दौरान और अधिक मदद करने के लिए अभिनव समाधान लेकर आए। कॉन्वेकके माध्यम से वे अब अपने सूक्ष्म शोध पत्र साझा कर सकते हैं। इन शोध पत्रों का विश्लेषण शिक्षाविदों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए शोध पत्र जनवरी, 2022 में निर्धारित %राष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी% के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने की और कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, नीति आयोग के सलाहकार (शिक्षा) डॉ. प्रेम सिंह,भारती फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल और भारती फाउंडेशन की सीईओ सुममता सैकिया ने भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय, एनआईईपीए के प्रतिनिधियों, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों/एससीईआरटी के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा, गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमने प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच हासिल कर ली है। कोविड 19 के कारण स्कूल बंद होने से अध्ययन की पुरानी अवस्था में पहुंचने के लिए यह एक तात्कालिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्वोक एक ऐसा मंच बन जाएगा जो अखिल भारतीय होगा और यह आनंदपूर्ण शिक्षण और अध्ययन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने में सुधार की दिशा में एक आंदोलन बन जाएगा। मैं सभी शिक्षा हितधारकों से हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक मिशन बनाने की अपील करता हूं। हमें प्री-स्कूल शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे प्री-स्कूल नहीं जा रहे हैं और इसलिए जब वे स्कूलों में प्रवेश करते हैं तो वे अध्ययन के परिणामों में पिछड़ जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके समाधान खोजने पर बहुत जोर देती है, शिक्षकों और छात्रों को 21वीं सदी के कौशल विकसित करने में मदद करती है। यह भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की कल्पना करता है, जिसमें स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति और आलोचनात्मक सोच पर जोर देने के साथ सीखने की अधिक खेल और खोज-आधारित शैली में निश्चित बदलाव शामिल है।